



INDIAN

POLITY

CTET - (P-2)

SST

BY - SUJEET BAJPAI SIR



Source → USA

Art (14-32)

Fundamental Rights



अनुच्छेद (3)

↓

Art =
12-35

The Fundamental Rights are enshrined in Part III of the Constitution from Articles 12 to 35.

In this regard, the framers of the Constitution derived inspiration from the Constitution of USA (i.e., Bill of Rights).

मौलिक अधिकार संविधान के भाग-III में अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रतिष्ठापित हैं ।

इस संबंध में संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान (यानी अधिकारों के विधेयक) से प्रेरणा प्राप्त की।

Originally, the Constitution provided for seven Fundamental Rights-

1. Right to equality (Articles 14–18)
2. Right to freedom (Articles 19–22)
3. Right against exploitation (Articles 23–24)

मूल रूप से संविधान में सात मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था-

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
3. शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

- 4. Right to freedom of religion (Articles 25–28)**
- 5. Cultural and educational rights (Articles 29–30)**
- 6. Right to property (Article 31)**
- 7. Right to constitutional remedies (Article 32)**

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
6. संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) - deleted
7. संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)

ORIG = ⑦

Present ⇒ ⑥

संपत्ति

However, the right to property was deleted from the list of Fundamental Rights by the 44th Amendment Act, 1978.

It is made a legal right under Article 300-A in Part XII of the Constitution. So at present, there are only six Fundamental Rights.

हालांकि, 44 वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था।

इसे संविधान के भाग 12वीं में अनुच्छेद 300-ए के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसलिए वर्तमान में केवल छह मौलिक अधिकार हैं ।

Features of Fundamental Rights:

1. Some of them are available only to the citizens.
2. ~~They are not absolute but qualified.~~ The state can impose reasonable restrictions on them.

मौलिक अधिकारों की विशेषताएं:

1. उनमें से कुछ केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।
2. वे निरपेक्ष नहीं बल्कि निर्बंधन के अधीन हैं। राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

X = 19 21 4

3. They are justiciable, allowing persons to move the courts for their enforcement, if and when they are violated.

4. They are defended and guaranteed by the Supreme Court. *f High Court*

3. वे Justiciable हैं, व्यक्तियों को उनके प्रवर्तन के लिए अदालतों में स्थानांतरित करने की अनुमति है, अगर और जब वे उल्लंघन कर रहे हैं ।

4. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका बचाव और गारंटी दी जाती है ।

Art 352

5. They can be suspended during the operation of a National Emergency except the rights guaranteed by Articles 20 and 21.

5. वे अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटी अधिकारों को छोड़कर एक राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है ।

~~6.~~ Their application to the members of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous services can be restricted or abrogated by the Parliament (Article 33).

6. सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अनुरूप सेवाओं के सदस्यों को उनके आवेदन को संसद (अनुच्छेद 33) द्वारा प्रतिबंधित या निरस्त किया जा सकता है ।

7. Fundamental rights can be restricted while martial law is in force in any area.

Martial law means 'military rule' imposed under abnormal circumstances to restore order (Article 34).

7. मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है जब मार्शल लॉ किसी भी क्षेत्र में लागू है।

मार्शल लॉ का मतलब है 'सैन्य शासन' (अनुच्छेद 34)।

1. Right
equality
(Articles
14-18)

(a) Equality before law and equal protection of laws
(Article 14).

(b) Prohibition of discrimination on grounds of religion,
to race, caste, sex or place of birth (Article 15).

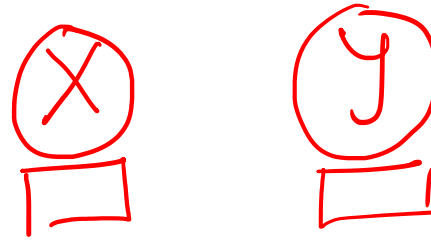
(c) Equality of opportunity in matters of public
employment (Article 16).

(d) Abolition of untouchability and prohibition of its
practice (Article 17).

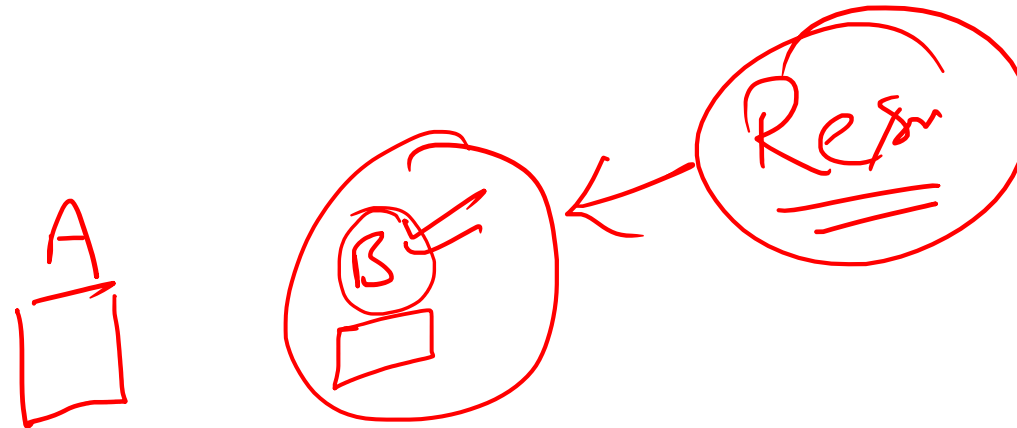
(e) Abolition of titles except military and academic
(Article 18).

↳ Hereditary titles (X)

समान
equality]



सम
equity] →



19(1)(a) ⑥
2. Right to freedom (Articles 19–22)

(a) Protection of six rights regarding freedom of: (i) speech and expression, (ii) assembly, (iii) association, (iv) movement, (v) residence, and (vi) profession (Article 19).

(b) Protection in respect of conviction for offences (Article 20).
→ दण्ड →

(c) Protection of life and personal liberty (Article 21).

(d) Right to elementary education (Article 21A).

(e) Protection against arrest and detention in certain cases (Article 22).
24Hrs

3. Right
against
exploitation
(Articles
23–24)

(a) Prohibition of traffic in human beings and forced labour (Article 23).

(b) Prohibition of employment of children in factories, etc. (Article 24).

4. Right to
freedom of
religion
(Article 25–
28)

(a) Freedom of conscience and free profession, practice
and propagation of religion (Article 25).

(b) Freedom to manage religious affairs (Article 26).

(c) Freedom from payment of taxes for promotion of any
religion (Article 27).

(d) Freedom from attending religious instruction or
worship in certain educational institutions (Article 28).



5. Cultural and
educational
rights
(Articles
29–30)

- (a) Protection of language, script and culture of minorities
(Article 29).
- (b) Right of minorities to establish and administer
educational institutions (Article 30).

6. Right to Right to move the Supreme Court for the enforcement of constitutional fundamental rights including the writs of (i) *habeas corpus*, remedies (ii) *mandamus*, (iii) prohibition, (iv) *certiorari*, and (v) *quo* (Article 32) *war-rento* (Article 32).

L. Ambedkar ⇒ Heart & Soul of
Indian Consti.
=

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

- (a) विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)।
- (b) धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)।
- (c) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16)।
- (d) अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध (अनुच्छेद 17)।
- (e) सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाए सभी उपाधियों पर रोक (अनुच्छेद 18)

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

- (a) छह अधिकारों की सुरक्षा (I) वाक् एवं अभिव्यक्ति, (II) सम्मेलन, (III) संघ, (IV) संचरण, (V) निवास, (VI) वृत्ति (अनुच्छेद 19)।
- (b) अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)।
- (c) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)।
- (d) प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21)।
- (e) कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22)।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

(a) बलात् श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23)।

(b) कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24)।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
- (a) अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)।
 - (b) धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)।
 - (c) किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)।

(d) कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)।

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
(अनुच्छेद 29-30)

- (a) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा (अनुच्छेद 29)।
- (b) शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार (अनुच्छेद 30)।

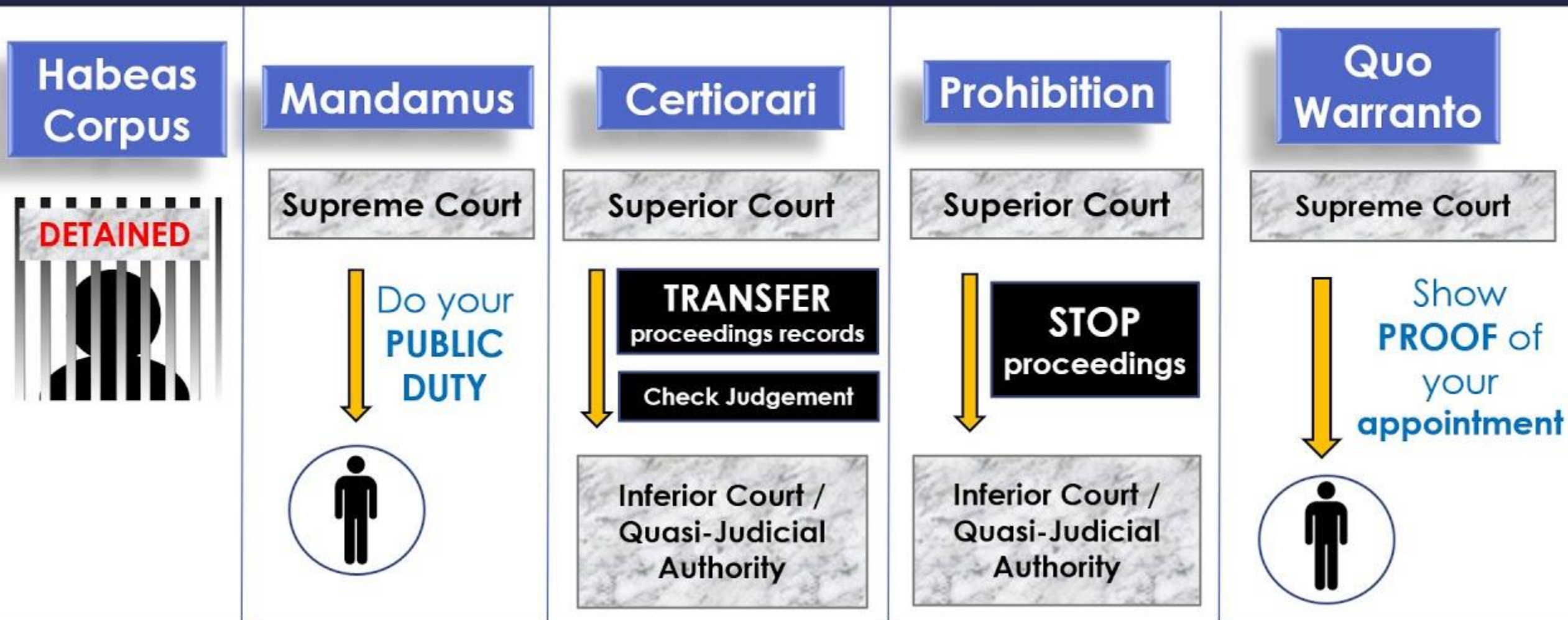
6. सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। इसमें शामिल याचिकाएं हैं—(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण, (ii) परमादेश, (iii) प्रतिषेध, (iv) उत्प्रेषण, (v) अधिकार पृच्छा (अनुच्छेद 32)।

WRIT
HABEAS CORPUS
MANDAMUS
PROHIBITION
CERTIORARI
QUO-WARRANTO

→ बंदी प्रत्यक्षीकरण
→ Bulwark of Individual Liberty
→ परमादेश
→ प्रतिषेध
→ (उत्प्रेषण)
→ अधिकार पूट है।

INDIAN POLITY – ⑤ WRITS



Right to Constitutional Remedies

Part-4

Ireland

Directive Principles of State Policy [DPSP]



सत्यमेव जयते

→ (Not
Justifiable
गैर वाज योय)

Part-4 ⇒ 36-51

**Article
No.**

Subject Matter

- | Article No. | Subject Matter |
|-------------|--|
| 36. | Definition of State |
| 37. | Application of the principles contained in this part |
| 38. | State to secure a social order for the promotion of <u>welfare</u> of the people |
| 39. | Certain principles of policy to be followed by the State |

मुफ्त न्याय

ग्राम पंचायतों की गठन

Amd-73rd

74th

- 39A. Equal justice and free legal aid
- 40. Organisation of village panchayats
- 41. Right to work, to education and to public assistance in certain cases = ल मनेगा
- 42. Provision for just and humane conditions of work and maternity relief
- 43. Living wage, etc., for workers
- 43A. Participation of workers in management of industries
- 43B. Promotion of co-operative societies
- 44. Uniform civil code for the citizens
- 45. Provision for early childhood care and education to children below the age of six years

Criminal Law

m / Ado / di /

- 46. Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections
- 47. Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health
- 48. Organisation of agriculture and animal husbandry
- 48A. Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife
- 49. Protection of monuments and places and objects of national importance
- 50. Separation of judiciary from executive
- 51. Promotion of international peace and security

अनुच्छेद संख्या	विषय-वस्तु
36.	राज्य की परिभाषा
37.	इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना।
38.	राज्य द्वारा जन-कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना
39.	राज्य द्वारा अनुसरण किये जाने वाले कुछ नीति-सिद्धांत
39.A	समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता
40.	ग्राम पंचायतों का संगठन
41.	कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता

- 42. न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान।
- 43. कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि
- 43.A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता
- 43.B. सहकारी समितियों को प्रोत्साहन
- 44. नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
- 45. बालपन-पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा
- 46. अनु. जाति, अनु. जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षिक, तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना

FR = 1 OPSP

- 47. पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन-स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने सम्बन्धी सरकार का कर्तव्य।
- 48. कृषि एवं पशुपालन का संगठन
- 48.A पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा
- 49. स्मारकों, तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण
- 50. न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव
- 51. अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन

New Directive Principles

The 42nd Amendment Act of 1976 added four new Directive Principles to the original list. They require the State:

1.

To secure opportunities for healthy development of children (Article 39).

नए निर्देशक सिद्धांत १९७६ के 42 वें संशोधन अधिनियम ने मूल सूची में चार नए निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा ।

उन्हें राज्य की आवश्यकता है:

1. बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करने के लिए (अनुच्छेद ३९) ।

2.

To promote equal justice and to provide free legal aid to the poor (Article 39 A).

3.

To take steps to secure the participation of workers in the management of industries (Article 43 A).

2. समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39ए)।

3. उद्योगों के प्रबंधन (अनुच्छेद 43ए) में कामगारों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना।

4.

To protect and improve the environment and to safeguard forests and wild life (Article 48 A).

The 44th Amendment Act of 1978 added one more Directive Principle, which requires the State to minimise inequalities in income, status, facilities and opportunities (Article 38).

4.

पर्यावरण की रक्षा और बेहतर बनाने के लिए और वनों और वन्य जीवन (अनुच्छेद ४८ ए) की रक्षा के लिए ।

१९७८ के ४४ वें संशोधन अधिनियम में एक और निर्देश सिद्धांत जोड़ा गया, जिसके लिए राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अंशों (अनुच्छेद ३८) में असमानता को कम करने की आवश्यकता है ।

The 86th Amendment Act of 2002 changed the subject-matter of Article 45 and made elementary education a fundamental right under Article 21 A.

The amended directive requires the State to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.

२००२ के ८६ वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद ४५ के विषय-वस्तु को बदल दिया और अनुच्छेद २१ ए के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया ।

संशोधित निर्देश में राज्य को छह वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है ।

The 97th Amendment Act of 2011 added a new Directive Principle relating to co-operative societies.

It requires the state to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of co-operative societies (Article 43B).

२०११ के ९७ वें संशोधन अधिनियम में सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देश सिद्धांत जोड़ा गया ।

इसके लिए राज्य को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी समितियों (अनुच्छेद ४३B) के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ।

Fundamental

↳ P-4A (+) 42nd / Amend / 1976
↳ सर्वो समिति =

Duties

↳ Source =

USSR

orig ⇒ 10

Present ⇒ ⑪

Preserve

Harmony

Respect

Cherish

Unity

Protect

FUNDAMENTAL DUTIES

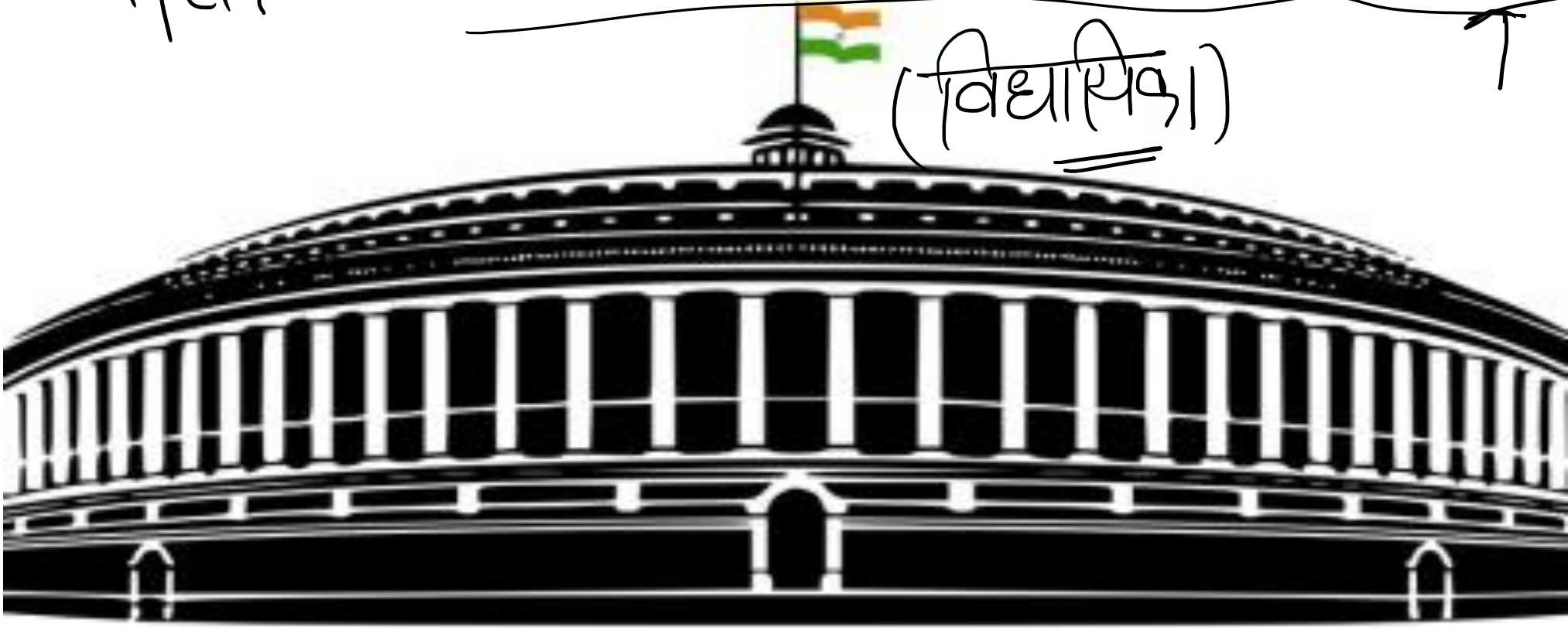
- 1** To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem
- 2** To cherish and follow noble ideals, which inspired our national struggle for freedom
- 3** To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India
- 4** To defend the country and render national service when called upon to do so
- 5** To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women
- 6** To value and preserve the rich heritage of our composite culture
- 7** To protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures
- 8** To develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform
- 9** To safeguard public property and to abjure violence
- 10** To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement
- 11** Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen

भारतीय संविधान

मौलिक कर्तव्य

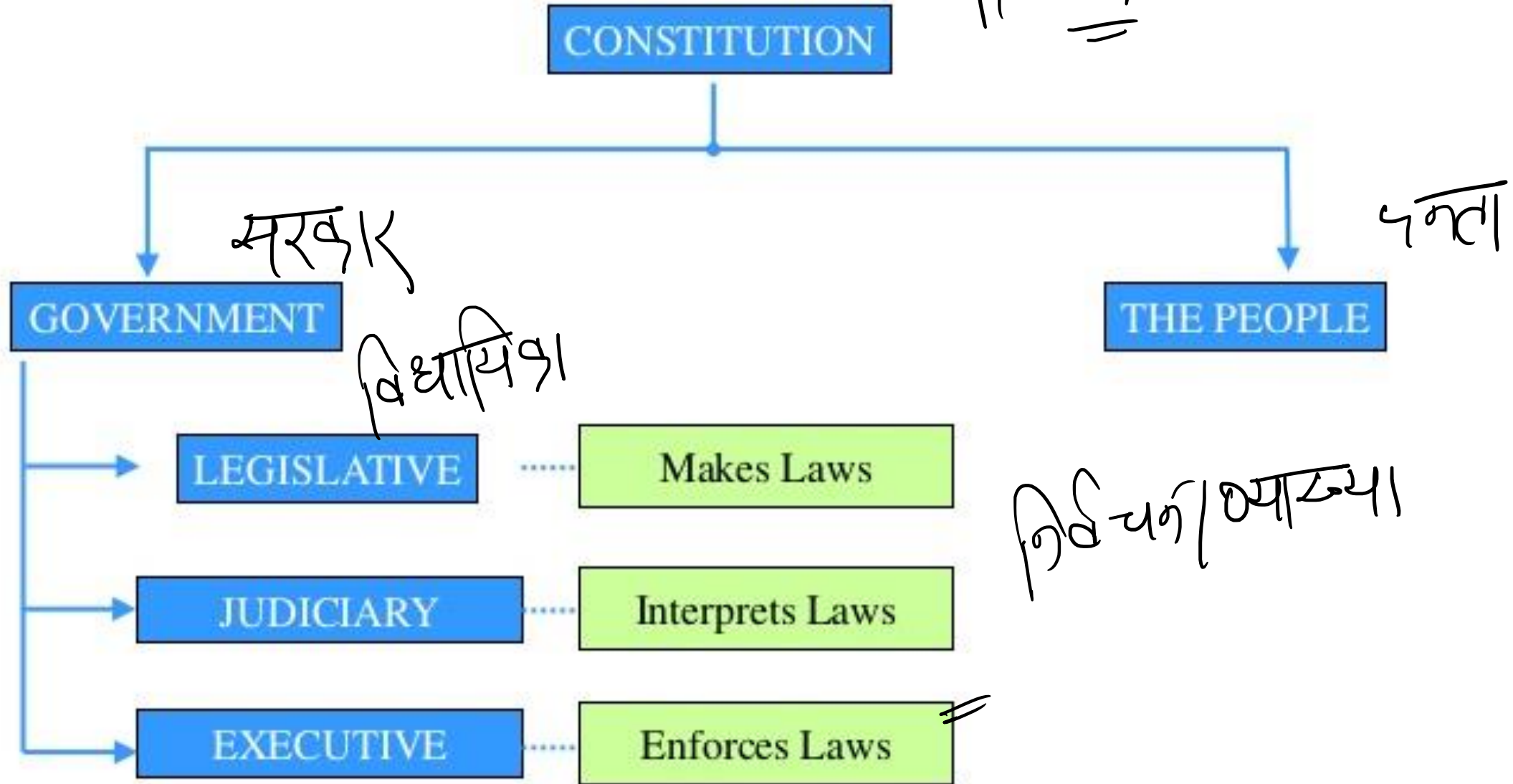
1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें।
4. देश की रक्षा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें।
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
11. माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

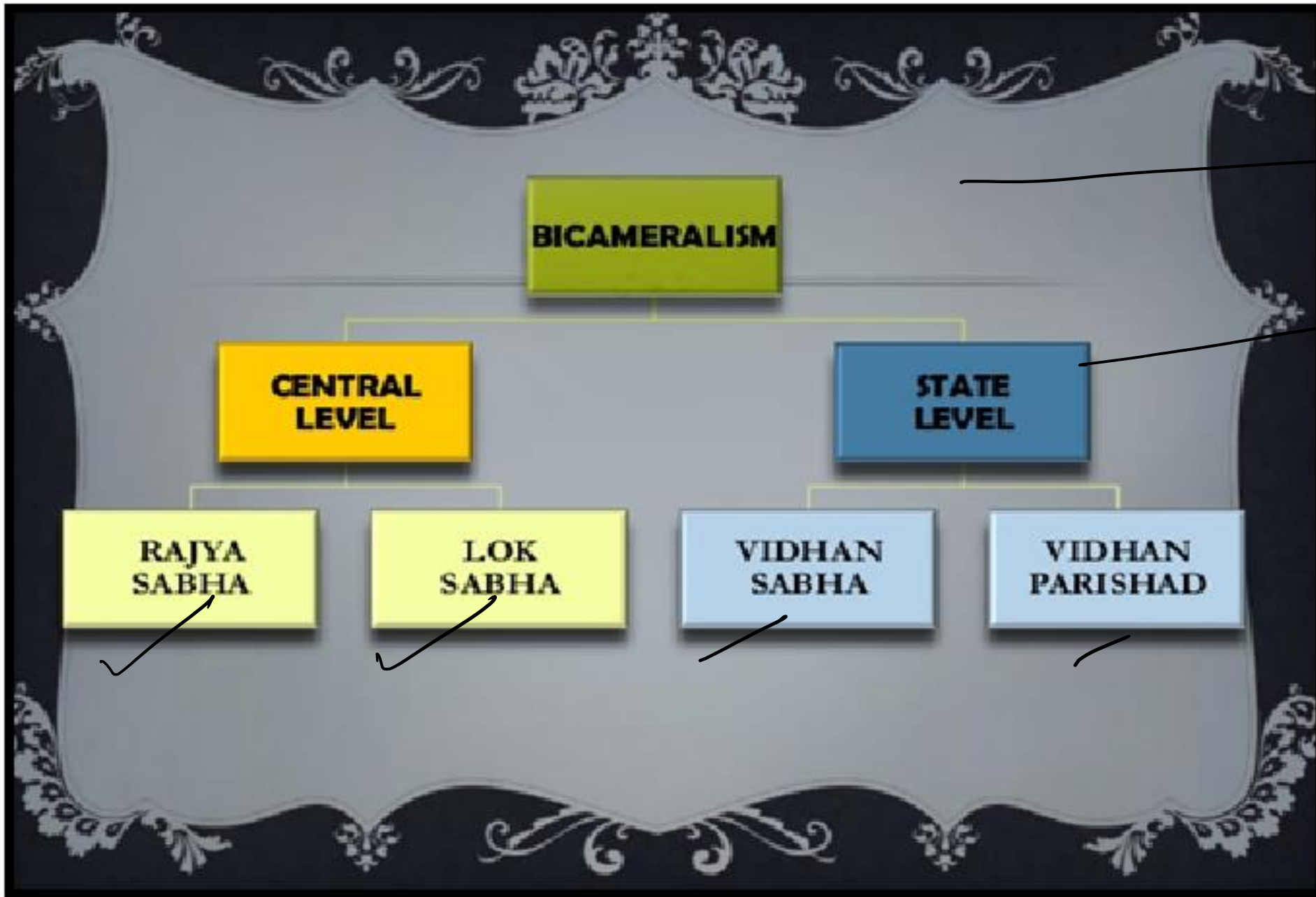
संसद = LS ⊕ RS ⊕ राष्ट्रपति President
(विधायिका)



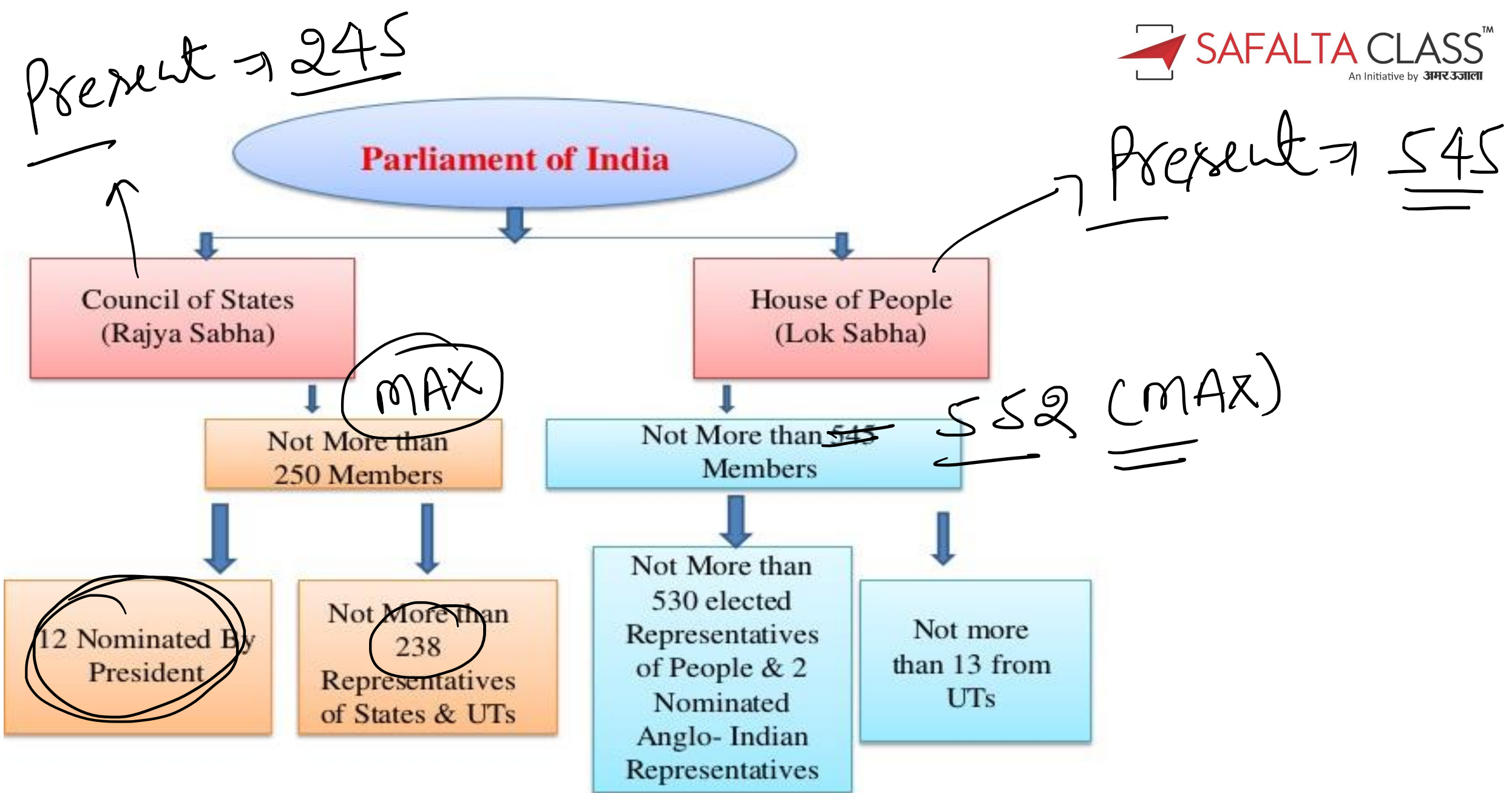
— PARLIAMENT OF INDIA —

संविधान





द्वि सदनीय
एक सदन
को सदन
[U.P. Bi]
[A.Tel]
[m.h.p]



Articles 79 to 122 in Part V of the Constitution deal with the organisation, composition, duration, officers, procedures, privileges, powers and so on of the Parliament.

संविधान के भाग V में अनुच्छेद 79 से 122 संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि के साथ संसद के साथ व्यवहार करते हैं।



Under the Constitution, the Parliament of India consists of three parts viz, the President, the Council of States and the House of the People.

In 1954, the Hindi names 'Rajya Sabha' and 'Lok Sabha' were adopted by the Council of States and the House of People respectively.

संविधान के तहत भारत की संसद में तीन भाग होते हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्य परिषद और जनता का घर ।

1954 में राज्य परिषद और जन सभा द्वारा क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा नाम अपनाए गए।

The parliamentary form of government emphasises on the interdependence between the legislative and executive organs.

Hence, we have the 'President-in-Parliament' like the 'Crown-in-Parliament' in Britain.

सरकार का संसदीय रूप विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच परस्पर निर्भरता पर जोर देता है ।

इसलिए, हमारे पास ब्रिटेन में क्राउन-इन-पार्लियामेंट की तरह ' राष्ट्रपति-इन-पार्लियामेंट ' है ।

The presidential form of government, on the other hand, lays stress on the separation of legislative and executive organs.

Hence, the American president is not regarded as a constituent part of the Congress.

दूसरी ओर, सरकार का राष्ट्रपति रूप विधायी और कार्यकारी अंगों के अलग होने पर जोर देता है ।

इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस का घटक हिस्सा नहीं माना जाता ।

Composition of Rajya Sabha

The maximum strength of the Rajya Sabha is fixed at 250, out of which, 238 are to be the representatives of the states and union territories (elected indirectly) and 12 are nominated by the president.

राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 तय है, जिसमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए) के प्रतिनिधि होने हैं और 12 राष्ट्रपति मनौनीत हैं।

At present, the Rajya Sabha has 245 members. Of these, 229 members represent the states, 4 members represent the union territories and 12 members are nominated by the president.

The Fourth Schedule of the Constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories.

फिलहाल राज्यसभा में 245 सदस्य हैं।

इनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।

The president nominates 12 members to the Rajya Sabha from people who have special knowledge or practical experience in **ART, LITERATURE, SCIENCE AND SOCIAL SERVICE.**

राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले लोगों से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं ।

The rationale behind this principle of nomination is to provide eminent persons a place in the Rajya Sabha without going through the process of election.

It should be noted here that the American Senate has no nominated members.

नामांकन के इस सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि चुनाव की प्रक्रिया से गुजरे बिना प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा में जगह प्रदान की जाए।

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमेरिकी सीनेट में कोई मनोनीत सदस्य नहीं है ।

Composition of Lok Sabha

The maximum strength of the Lok Sabha is fixed at 552.

Out of this, 530 members are to be the representatives of the states, 20 members are to be the representatives of the union territories and 2 members are to be nominated by the president from the Anglo-Indian community.

लोकसभा की संरचना लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 तय है। इसमें से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होने हैं, 20 सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि होना है और (2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति मनोनीत किया जाना है।)

समाप्त
2019

At present, the Lok Sabha has 545 members. Of these, 530 members represent the states, 13 members represent the union territories and 2 Anglo-Indian members are nominated by the President.

वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 एंग्लो-इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

Term X

(कार्यकाल) ←

Duration of Two Houses

Duration of Rajya Sabha:

→ Permanent House
→ dissolved (X)

The Rajya Sabha (first constituted in 1952) is a continuing chamber, that is, it is a permanent body and not subject to dissolution.

राज्यसभा की अवधि:

→ (Term of members ⇒ 6 yrs)

राज्यसभा (पहली बार 1952 में गठित) एक सतत कक्ष है, अर्थात् यह एक स्थायी निकाय है।

However, one-third of its members retire every second year.

Their seats are filled up by fresh elections and presidential nominations at the beginning of every third year.

हालांकि इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते हैं।
उनकी सीटें हर तीसरे साल की शुरुआत में नए चुनाव और राष्ट्रपति पद के नामांकन से भरी जाती हैं।

→ Temp. House — 5yrs

Unlike the Rajya Sabha, the Lok Sabha is not a continuing chamber.

Its normal term is five years from the date of its first meeting after the general elections, after which it automatically dissolves.

लोकसभा की अवधि राज्यसभा के विपरीत लोकसभा का कोई सदन जारी नहीं है।

इसका सामान्य कार्यकाल आम चुनाव के बाद अपनी पहली बैठक की तारीख से पांच साल का होता है, जिसके बाद यह अपने आप घुल जाता है।

5th LS \Rightarrow (5 yrs)

10 months

However, the President is authorised to dissolve the Lok Sabha at any time even before the completion of five years and this cannot be challenged in a court of law.

हालांकि राष्ट्रपति पांच साल पूरे होने से पहले ही किसी भी समय लोकसभा भंग करने के लिए अधिकृत हैं और इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

Further, the term of the Lok Sabha can be extended during the period of national emergency be a law of Parliament for one year at a time for any length of time.

However, this extension cannot continue beyond a period of six months after the emergency has ceased to operate.

इसके अलावा, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है संसद का कानून किसी भी समय एक समय में एक वर्ष के लिए होता है।

हालांकि, आपातकाल के संचालन के बाद यह विस्तार छह महीने की अवधि से आगे जारी नहीं रह सकता ।

Qualifications

The Constitution lays down the following qualifications for a person to be chosen a member of the Parliament:

1. He must be a citizen of India.
2. He must make and subscribe to an oath or affirmation before the person authorised by the election commission for this purpose. In his oath or affirmation, he swears
 - (a) To bear true faith and allegiance to the Constitution of India
 - (b) To uphold the sovereignty and integrity of India
3. He must be not less than 30 years of age in the case of the Rajya Sabha and not less than 25 years of age in the case of the Lok Sabha.
4. He must possess other qualifications prescribed by Parliament.

The Parliament has laid down the following additional qualifications in the

Question Hour

प्रश्न काल



विधायिका, सरकार को नियंत्रित करती है।

The first hour of every parliamentary sitting is slotted for this. During this time, the members ask questions and the ministers usually give answers. The questions are of three kinds, namely, starred, unstarred and short notice.

तारांकित *

A **starred question** (distinguished by an asterisk) requires an oral answer and hence supplementary questions can follow.

An **unstarred question**, on the other hand, requires a written answer and hence, supplementary questions cannot follow.

A **short notice question** is one that is asked by giving a notice of less than ten days. It is answered orally.

कल्प सूचना प्रश्न

Zero Hour → शून्य घण्टा → media → Indian Innovation (नवाचार)

Unlike the question hour, the zero hour is not mentioned in the Rules of Procedure. Thus it is an informal device available to the members of the Parliament to raise matters without any prior notice. The zero hour starts immediately after the question hour and lasts until the agenda for the day (ie, regular business of the House) is taken up. In other words, the time gap between the question hour and the agenda is known as zero hour. It is an Indian innovation in the field of parliamentary procedures and has been in

- ① Question Hour
- ② Zero Hr
- ③ Agenda of day

अविश्वास प्रस्ताव ⇒

No-Confidence Motion Article 75 of the Constitution says that the council of ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. It means that the ministry stays in office so long as it enjoys confidence of the majority of the members of the Lok Sabha. In other words, the Lok Sabha can remove the ministry from office by passing a no-confidence motion. The motion needs the support of 50 members to be admitted.

○ Opposition